SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. SESSION – 21-23

SUBJECT - C-02

TOPIC NAME – लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति

DATE - 19-01-22

PAGE NO.
DATE :

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति
Lord Curzon's Education Policy

19 वीं शताब्दी के अन्तिम समय में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय, जनवरी 1899 को भारत के नए गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन आए। लार्ड कर्जन विद्वान कुशल प्रशासक और पाश्चात्य सभ्यता का पोषक था। इनका मत था कि शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जा सकता है। इसके लिए उसने सर्वप्रथम 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन किया तथा कुछ शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित कराया जिनका विवरण निम्नलिखित है।

शिमला शिक्षा सम्मेलन – 1901

सम्मेलन का आयोजन —

भारत में शैक्षिक सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए 1901 में शिमला में भारत के उच्च शिक्षा और वि० वि० अधिकारियों का एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे शिमला सम्मेलन या शिमला अकार्ड कहा जाता है। इस सम्मेलन में प्रत्येक प्रान्त के शिक्षा संचालक एवं मिशनरियों के प्रतिनिधि को ही शामिल किया गया। भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया था।

यह सम्मेलन 15 दिनों तक चला जिसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए।

शिक्षा नीति —

सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के आधार पर निम्न शिक्षा नीति निर्धारित की की।

1) सरकार अभी शिक्षा से अलग नहीं होगी समस्त क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण बना रहेगा।
2. आवश्यकतानुसार सरकारी विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
3. सरकार पहले से अधिक धन शिक्षा पर व्यय करेगी।

भारतीय वि॰वि॰ आयोग 1902

नियुक्ति के कारण —

कर्जन का विचार था कि भारतीय वि॰वि॰ में सुधार की आवश्यकता है। 1848 में लन्दन वि॰वि॰ का नवीनीकरण करना जरूरी था कॉलेजों की सं॰ में वृद्धि हो गई थी। शिक्षकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। कॉलेजों का शिक्षा स्तर गिर गया था। इन सभी कारणों के जाँच करने के लिए 27 जनवरी 1902 को आयोग की नियुक्ति की गई। जिसके अध्यक्ष सर थामस रेले थे।

PAGE NO.
DATE :

जाँच के विषय (Terms of Referance)

वि॰वि॰ की दशा एवं उनकी उन्नति की जाँच करना उनके कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना एवं ऐसे उपाय सुझाना जिनसे वि॰वि॰ का शिक्षण स्तर उपर उठ सके।

आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियाँ (Suggestions and Recomendations of of the commission) —

प्रशासन एवं संगठन —

(1) सीनेट एवं सिण्डिकेट का पुनर्गठन आवश्यक है सीनेट की सं॰ कम कर दी जाए और उनका अवधि 5 वर्ष तथा सिण्डिकेट के सदस्यों की सं॰ 5 से 15 तक रखी जाए।

2 प्रत्येक वि॰वि॰ का अधिकार क्षेत्र निश्चित कर दिया जाए।

शिक्षण व्यवस्था (Arrangement of Teaching)

(1) विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

2. पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए।

3. वि॰वि॰ की परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन कार्य में विशेष सुधार किए जाएं।

आयोग के गुण Merits of Commission

1. आयोग ने वि० वि० में सीनेट के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी और उनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया जिससे वि०वि० के प्रशासन एवं संगठन में स्थिरता आ गई।

2. कॉलेजों एवं वि० वि० के प्राध्यापकों एवं सुयोग्य विद्वानों को प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया।

3. सिण्डीकेट के सदस्यों की सं० में वृद्धि करने की संस्तुति की थी जिससे अधिक लोगों को सीनेट में प्रतिनिधित्व मिलने लगा।

4. आयोग ने वि०वि० एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों परीक्षा प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया।

दोष — (Demerits)

1. महाविद्यालयों को सम्बद्धता हेतु नियम कठोर कर देने से महाविद्यालयों की स्थापना में कमी आ गई।

2. आयोग ने महाविद्यालयों में शिक्षण को स्नातक स्तर तक ही सीमित रखा।

3. सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियमित निरीक्षण से वि०वि० के आन्तरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि हुई।

4. निम्न स्तर के महाविद्यालयों को बंद करने की संस्तुति भी दोषपूर्ण।

PAGE NO.
DATE :

सम्बद्ध महाविद्यालय (Affiliated colleges

(1) महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के नियम कठोर रखी जाए।
2. मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए।
3. महाविद्यालयों में स्नातक स्तर का शिक्षण होना चाहिए।
4. निम्न कोटि के महाविद्यालयों को बंद कर दिया जाए।
5. मैट्रिकुलेशन का स्तर उन्नत किया जाए। इण्टरमीडिएट कक्षाएँ समाप्त की जाए। और स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाए।
6. वि.वि० द्वारा सम्पादित परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में पर्याप्त सुधार किया जाए।

गुण + दोष

शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव 1904

11 मार्च 1904 को लार्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का सूक्ष्म विश्लेषण दो दृष्टियों से किया गया है।

(1) संख्यात्मक दृष्टि से शिक्षा के दोष — 6 में से 5 गाँवो में स्कूल नहीं है। चार बालको में तीन अशिक्षित हैं और 40 में से 1 बालिका किसी प्रकार से स्कूल में शिक्षा प्राप्त

करती है।

2 गुणात्मक दृष्टि से प्रस्ताव में शिक्षा के दोष

(1) उच्च शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना है।
2. पाठ्यक्रम पूर्णतया साहित्यिक है।
3. स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की बुद्धि का विकास कम किया जाता है और स्मृति का अधिक
4. अंग्रेजी भाषा को प्रधानता देकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जाती है।

उपर्युक्त दोषों के निराकरण हेतु शिक्षा के सभी क्षेत्रों निम्नलिखित सरकारी नीति घोषित की गई।

प्राथमिक शिक्षा —

1 प्राथमिक शिक्षा का विकास करना सरकार का मुख्य कर्तव्य होगा।
2 पाठ्यक्रम में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3 अंग्रेजी भाषा की शिक्षा 13 वर्ष के बाद दी जायेगी।
4. शिक्षण विधियों में सुधार और किण्डर गार्टन विधि का उपयोग किया जायेगा।
5. बालिकाओं के शिक्षा के लिए अधिक प्राथमिक शालाएं खोली जायेंगी।

माध्यमिक शिक्षा

PAGE NO.
DATE :

1 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण स्तर को बढ़ाने के लिए निरीक्षण का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा।

2 पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया जायेगा।

3. प्रत्येक जिले में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जायेगा।

4. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा।

वि० वि० शिक्षा —

1 उच्च शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार और उन्नति के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जायेगा।

2. वि० वि० शिक्षा में बाह्य परीक्षाओं के प्रमुखत्व को कम किया जायेगा।

कर्जन के शिक्षा संबंधी अन्य प्रयास भी रहे जैसे —

(1) केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना कृषि शिक्षा की व्यवस्था, पुरातत्व ऐतिहासिक भवनों, स्मारकों के संरक्षण विभाग की स्थापना विदेशों में अध्ययन रत छात्रों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन

अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों एवं संकीर्ण

पहले से ही असंतुष्ट थे। 20 जुलाई 1905 में लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन को भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीयता में और उबाल ला दिया। इससे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और उग्र रूप धारण कर लिया। उसी समय में ही रौलेट एक्ट बना जिसे नेताओं ने लगा कि सरकार लोगों की उचित मांग को दबाने की प्रयास कर रही है। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया इससे जनता में और आक्रोश व्याप्त हो गया। 19 वीं शताब्दी में यूरोप तथा अन्य देश में राष्ट्रीय आंदोलन चले इनसे भारतीय को प्रेरणा एवं आत्मबल मिली। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 ई० को कोलकता अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। जिसे बाद में स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। इस अधिवेशन में चार प्रमुख प्रस्ताव पारित किये गए थे —

(1) स्वराज की प्राप्ति (Attainment or self Government)
(2) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार (Boycott of British Goods)
(3) स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग (use of Native Goods)
(4) राष्ट्रीय शिक्षा की मांग (Demand of National Education)

PAGE NO.
DATE :

राष्ट्रीय शिक्षा के विशेषताएँ या सिद्धांत :—

7 अगस्त 1905 ई० को हुए कोलकता अधिवेशन में राष्ट्रीय नेताओं तथा शिक्षाशास्त्रियों के बीच तथा विमर्श के बाद राष्ट्रीय शिक्षा के निम्नलिखित विशेषताएँ या आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किये गये।

1. शिक्षा भारतीयों के नियंत्रण में हो शिक्षा की संरचना, संगठन एवं संचालन का अधिकार भारतीयों को हो।

श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा— "भारतीय शिक्षा भारतवासियों द्वारा नियंत्रित भारतवासियों द्वारा निर्मित और भारतवासियों द्वारा संचालित होनी चाहिए।"

2. अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम और अनिवार्य न बनाया जाये। इसके स्थान पर मातृ-भाषाओं को शिक्षण का माध्यम बनाया जाये।

3. शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श संस्कृति पर आधारित हो।

4. पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों का समावेश हो।

5. यूरोपीय भाषाओं साहित्यों एवं विज्ञानों के अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया जाये।

इस संदर्भ में लाला लाजपतराय ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया —

PAGE NO.
DATE :

"मैरे विचार से भारत में यूरोपीय भाषाओं, साहित्यों एवं विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहित न करने का प्रयास मूर्खता एवं पागलपन होगा।"

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना :-

इस दिशा में प्रथम प्रयास बंगाल में हुआ श्री गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में 15 - अगस्त 1906 ई० को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। रास बिहारी घोस और रविन्द्र नाथ टैगोर आदि राष्ट्रीय नेता इससे सम्बद्ध हो गए। कुछ समय में ही इस समिति के पास लाखों रुपये जमा हो गए, जिससे उसने निम्न कार्य किए :—

1. राष्ट्रीय शिक्षा के लिये प्राथमिक शिक्षा से लेकर बि० ए० तक की शिक्षा के विकास की योजना तैयार की।

2. पश्चिम बंगाल में 11 और पूर्वी बंगाल में 40 माध्यमिक विद्यालय खोले गए।

3. समिति ने कलकत्ता में नेशनल कॉलेज स्थापित किया। श्री अरविन्द घोष को इसका प्रिंसिपल बनाया।

4. कलकत्ता में ही एक टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट खोला जो बाद में जादवपुर कॉलेज

ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हुआ। (Technical Institute Jadavpur college of engineering and Technology)

इस प्रकार से थोड़े ही समय में सम्पूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय विद्यालयों का जाल बिछ गया, आर्य प्रतिनिधि सभा ने वृंदावन और हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किये और अन्य स्थानों पर दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किये गये।

"राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का प्रभाव:—

सन 1906 ई० में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1920 ई० में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामियां एवं अलीगढ़ की स्थापना की गई। इसके अलावा देश के अन्य भागों में मुस्लिम शिक्षा संस्थाएं खोली गई।

पूना में नारी वि० वि० की स्थापना, महात्मा गाधी की वर्धा योजना, रवीन्द्रनाथ टैगोर की शान्ति निकेतन, हीरालाल शास्त्री की वन स्थली, विद्यापीठ, अरविन्द घोष का अरविन्द आश्रम आदि शिक्षा संस्थाएं खोली गई।